1. Title Of The Thesis

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा के कार्यो का मूल्यात्मक अध्ययन
(राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

2. Introduction

ग्रामीण गरीबी :–

भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि के आधारभूत कार्यो से अपना जीवन यापन करती है, परंतु कृषि कार्यो को आधुनिक भारत में पेशे का स्वरूप न देकर इसे मौसमी कार्यो का स्वरूप दिया गया है, अर्थात् एक ग्रामीण अपनी कृषि के कार्यो के पश्चात् बेरोजगारी का सामना करता है और यहीं से वह गरीबी की ओर अग्रसर होता जाता है। ग्रामीण किसान रोजी–मज़दूरी करके हम सभी के लिए अन्न उगाते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ को योजना आयोग द्वारा भारत का सबसे गरीब राज्य घोषित किया गया।

"ग्रामीण गरीबी रेखा का तात्पर्य आय के उस स्तर से लिया जाता है जिसमें आय कम होने पर ग्रामीण अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता"।

गरीबी अथवा निर्धनता का अर्थ उस स्थिति से जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करनें में असमर्थ रहता है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :–

भारत में व्याप्त गरीबी को ध्याान में रखकर सरकार द्वारा समय समय पर जो योजना या कार्यक्रम बनाये जाते है उन कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन या गरीबी निवारण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। सरकार ने गरीबी हटानें के लिये वर्तमान में निम्नलिखित योजनांएं लागू की है :–

1- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना (S.G.S.Y.)

2- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (S.J.S.R.Y.)

3- प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (P.M.G.Y.)

4- प्रधान मंत्री रोजगार योजना (P.M.R.Y.)

5- इंदिरा गांधी आवास योजना (I.A.Y.)

6- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (S.R.G.Y.)

7- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (N.S.A.P.)

8- कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (K.S.S.S.Y.)

9- सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम (D.P.A.P.)

10- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (M.G.N.R.E.G.A.)

अध्ययन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम

1. अपंग छात्रवृत्ति योजना
2. कृत्रिम अंग उपकरण/दीन दयाल निःशुल्क पुनर्वास कार्यक्रम
3. गृह लक्ष्मी योजना
4. सुखद सहारा योजना
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
6. छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना (नवा अंजोरा)

ग्रामीण गरीबी एवं मनरेगा :–

ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी से उत्पन्न दयनीय स्थिति को देखते हुए उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सन् 2005 मे राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 का उदय हुआ, जिसे आज हम **मनरेगा** के नाम से जानते हैं।

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 हैं। इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 देश का पहला अधिनियम है जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासियो को गाँव मे ही रोज़गार उपलब्ध कराता है। फरवरी 2006 से लागू इस अधिनियम के तहत् ग्रामीण क्षेत्रो के प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन का शारीरिक श्रम युक्त रोज़गार पाने का अधिकार है। यह उल्लेखनीय है कि गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2009) के अवसर पर केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस अधिनियम को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा जाए। अब नरेगा **'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम'** के नाम से जाना जाने लगा। अकुशल शारीरिक श्रम से कोई कार्य अभिप्रेत है जिसे कोई वयस्क पुरूष या महिला किसी कौशल या प्रशिक्षण के बिना भी करने मे समर्थ हो। मनरेगा कुछ ऐसे बिंदुओं पर बल देता है जो काम के अधिकार को व्यापक स्तर पर चरितार्थ करता है।

मनरेगा

SELF		HELP		GROUP	
S =	**Saving** बचत	H =	**Honesty** ईमानदारी	G =	**Growth** वृद्धि
E =	**Empowerment** शक्ति	E =	**Employment** रोजगार	R =	**Resource** स्त्रोत
L =	**Learning** सीखना	L=	**Leadership** नेतृत्व	O =	**Oppportunity** अवसर
F =	**Friendship** दोस्ती	P =	**Pramoted** प्रोत्साहन	U =	**Unity** एकता
				P =	**Progress** प्रगति

राजनांदगॉव जिला :–

26 जनवरी सन् 1973 को दुर्ग जिले के विभाजन के बाद राजनांदगाँव जिला अस्तित्व मे आया। राजनांदगाँव क्षेत्र सोमवंशियो, कल्चुरियों एवं मराठा शासको द्वारा शासित था। राजनांदगाँव का प्रारंभिक नाम नंदग्राम था। राजनांदगाँव नगर के महल एवं भवन यहाँ के शासको के शासन, यहाँ के समाज, संस्कृति एवं उस समय की शानदार परम्परा की कहानी का वर्णन करते है। कुछ वर्षो पश्चात 1 जुलाई स्न 1998 को कवर्धा जिला राजनांदगाँव से विभक्त हो गया।

3. A Brief Review Of The Work Already Done In The Field

संबंधित साहित्य का अध्ययन

एक शोधकर्ता का उचित मार्गदर्शन उसके विषय से संबंधित साहित्य ही कर सकता है क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि पुस्तकें ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है।

विषय की गहराई तक पहुँचने के लिए शोधकर्ता ने संबंधित साहित्य का गहन अध्ययन किया है। अध्ययन के पश्चात् ही गहन चिंतन कर विषय से संबंधित साहित्य के निष्कर्ष को समझा एवं अपने विषय से संबंधित लेखन एवं आंकलन का ढांचा तैयार किया जाता है ।

1. **kannapioram(1992)** द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मुलन योजना का ग्रामीण निर्धनता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना में सतत रोजगार के कारण ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार आया ।

2. **Jaswal Anshuman(2003)** द्वारा महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किये जाने वाले दैनिक भुगतान के बारे में लाभार्थियों की जानकारी का अध्ययन किया । यह अध्ययन दिशा, अहमदाबाद में किया गया था । अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि लाभार्थियों के जॉब कार्ड प्रायः सरपंच द्वारा अपने पास रख लिये जाते है जिससे लाभार्थियों को कार्य के बदले मिलने वाले भुगतान की जानकारी नहीं होती है एवं समान कार्य के लिए अलग–अलग गॉवों में भुगतान भिन्न–भिन्न दर से किया जाता है ।

3. **Dreze(2006)** द्वारा महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में एक अध्ययन किया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि राजस्थान में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में चलाये जा रहे कार्यो में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिये अनुकुल सुविधाएँ मौजूद नहीं है तथा कार्यस्थल पर उचित मेडिकल एवं कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिए कोई सुविधाएँ नहीं है। अधिकांश स्थानों पर द्वारा महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत महिलाओं को अपने बच्चों को धूप में ही रखना पड़ता है या फिर उन्हे घर पर ही छोड़कर आना पड़ता है जिससे उनकी पारिवारिक समस्याओं में वृद्धि होती है।

4. **CAG(2007)** ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किये अध्ययन में यह पाया कि मरनेगा के कियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की अत्यंत कमी है तथा इस की को तुरंत दूर किया जाना चाहिए जिससे मरनेगा का सही कियान्वयन हो सके। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पंजीकृत परिवारों में से केवल 3.2 प्रतिशत परिवारों को ही 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया गया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देने में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण है ।

5. Anand(2008)) ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर किये अध्ययन में पाया कि योजना के क्रियान्वयन में कई त्रुटियॉ थीं जिनमें मुख्य रूप से कार्यरत महिलाओं के बच्चों के लिये कार्यस्थल पर किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध न होना मुख्य था।

6. Garg(2008) ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्य करने से उन्हे पारिवारिक समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ा किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में सार्थक बदलाव हुआ।

7. Prasad, M.R.(2008) ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की गॉवों से पलायन करने की प्रवृति पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा सार्थक स्तर पर पलायन को रोकने में मदद मिली है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लाभ लाभार्थियों की आय पर सार्थक रूप से दृष्टिगोचर हुआ। नकारात्मक पहलू के रूप में यह तथ्य भी सामने आया कि कई जॉब कार्डधारियों को 15 दिनों तक कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ और न ही उन्हें कोई बेरोजगारी भत्ता ही प्राप्त हुआ।

8. Vesha joshi and singh(2008) ने राजस्थान महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् पलायन की प्रवृति में कुछ कमी जरूर आयी किन्तु इसे पूरी तरह रोका नहीं जा सका। अध्ययन से यह तथ्य भी सामने आया कि मरनेगा के क्रियान्वयन के पश्चात् हितार्थियों की आय में बढ़ोतरी हुई तथा ग्रामीण द्वारा साहूकारों से लिये जा रहे कर्ज में भी कमी आयी है।

9. Ambasta(2008) ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध सरकारी कर्मचारीयों के संबंध में एक अध्ययन किया। अध्ययन से प्रााप्त परिणामों के अनुसार ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में कर्मचारियों की कमी एक प्रमुख समस्या है तथा मनरेगा के सशक्त क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर, तालुका स्तर एवं गॉव स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

10. CSE(2008) ने मनरेगा के क्रियान्वयन में चुनौतियॉ एवं अवसर पर एक अध्ययन किया। अध्ययन में यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने में उतना प्रभावशाली नहीं हुआ है जितनी कि महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अपेक्षा थी। अध्ययन से यह भी पाया गया कि मनरेगा में लाभार्थी द्वारा आर्थिक दोहन किया जा रहा है न कि एक ऐसी आर्थिक क्रांति जिसमें श्रमिकों की अधिकता से उत्पादन एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही हो। अध्ययन में यह तथ्य भी सामने आया कि स्थानीय नौकरशाही मनरेगा के क्रियान्वयन में बाधक तत्व है जिससे इस योजना का सीधा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

11. Siddhanta,P.(2008) ने अपने लेख में मनरेगा पर योजना आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण किया। इसके अनुसार केवल 14 प्रतिशत परिवारों को योजना के अंतर्गत 100 दिन रोजगार प्रदान किया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और केरल ने मरनेगा के तहत औसत 22 दिन का रोजगार प्रत्येक पंजीकृत परिवार को उपलब्ध कराया वहीं पश्चिम बंगाल एवं बिहार में 26 दिन रोजगार उपलब्ध कराया। गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल एवं बिहार देश में मनरेगा के कियान्वयन में सबसे पिछड़े हुए थे।

12. Vanik(2008) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर हजारीबाग(झारखंड) में एक अध्ययन किया। अध्ययन में यह पाया गया कि हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, साथ ही भुगतान में भी 40 से 50 दिनों का विलंब होता था जिसकी वजह से हितग्राही महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को छोड़कर जाने हेतु ऐसे स्थानों पर जाने को विवश थे जहॉ कार्य के पश्चात् तुरंत भुगतान की व्यवस्था थी।

13. Rrrtika khera(2009) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में महिलाओं के विचार जानने के उद्‌देश्य से अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगारप्राप्त हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाऍ केरल, राजस्थान एवं तमिलनाडु राज्य में थी जबकि आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरप्रदेश में एक तिहाई से कम महिलाऍ मनरेगा के अंतगर्त कार्यरत थी। अध्ययन में चयनित महिला हितग्राहियों में से अधिकांश का यह विचार था कि मनरेगा में रोजगार प्राप्त होने के पश्चात् उनका परिवार भुखमरी की समस्या से उबर रहा है। उत्तरदाताओं में से 68 प्रतिशत महिलाओं का मानना था मरनेगा का अनके जीवन में अत्यधिक महत्व है।

14. Chakravarthy(2010) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन में गुजरात में हुई अनियमितता पर विश्लेषण किया। लेख के अनुसार siddhanta,P. (2008) ने अपने लेख में मरनेगा हेतु आबंटित राशि को गुजरात सरकार ने वन विभाग को परिवर्तित कर दिया। रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित किया गया कि गुजरात में हितग्राहियों को मनरेगा के तहत किये जाने वाले भुगतान में 03 से 06 माह की देरी हुई।

15. Rengaswamy and Sasi kumar(2011) महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हुए कार्यो का राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश में मनरेगा के तहत 50 प्रतिशत परिवारों को लाभ मिला जिसका सीधा प्रभाव यहॉ के लाभांवितों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा क्योंकि छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश दोनों ही राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय औसत के अधिक है। मनरेगा के तहत आबंटित राशि का उपयोग सर्वाधिक मध्यप्रदेश, आंधप्रदेश एवं राजस्थान में किया गया जिसके पश्चात् आंबटित राशि का उपयोग उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं बिहार द्वारा किया गया।

16. **Badodiya et al.(2011)** महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का गरीबी उन्मुलन के संदर्भ में अध्ययन किया। अध्ययन हेतु ग्वालियर जिले के मोरार ब्लॉक के 110 ग्रामीण लाभार्थी जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के थे, का चयन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के मनरेगा में कार्य करने से लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति में सार्थक सुधार हुआ। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि मनरेगा में कार्य के दौरान अधिकारीयों से संपर्क में आने से लाभार्थियों का शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, लोन सुविधा के बारे में जानकारी में भी सार्थक वृद्धि हुई।

17. **Honnakeri and Kote(2012)** ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने गॉव से पलायन की समस्या एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन हेतु गुलबर्गा जिले के दो गॉवों कोडला एव कुसनुरू से आंकड़ो का संकलन किया गया। अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत रोजी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर कर दिया गया एवं इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। अध्ययन में यह पाया गया कि मनरेगा में कार्यरत प्रतिशत लोग मनरेगा के विषय में अनभिज्ञ थे। अध्ययन से प्राप्त महत्वपूर्ण परिणाम में यह ज्ञात हुआ कि मनरेगा के प्रारंभ होने के पश्चात् ग्रामीणों की पलायन की प्रवृति घटी जिसका मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार था।

4. Objective

शोध का उद्देश्य

किसी भी शोध कार्य में सफलता का सार्थक परिणाम प्राप्त करनें हेतु उस शोध का पूर्ण तथा निर्धारित लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके आधार पर शोध कार्यों को एक व्याापक गति प्रदान की जाती है।

प्रस्तावित अध्ययन राजनांदगांव जिले में **मनरेगा** योजना के द्वारा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन विश्लेषण पर आधारित है। जिसके **उद्देश्य** निम्नलिखित है :–

- राज़नाँदगाँव जिले मे **मनरेगा** से प्राप्त रोजगार का अध्ययन करना
- राज़नांदगाँव जिले मे **मनरेगा** योजना से क्षेत्र विशेष के विकास पर प्रभावो का अध्ययन करना
- . राजनांदगांव जिले में **मनरेगा** द्वारा किये गये कार्यों का अध्ययन करना
- गरीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान पर **मनरेगा** का प्रभाव
- **मनरेगा** योजना की समस्याओं का पता लगाना
- अध्ययन क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के कार्यों व विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना
- **मनरेगा** योजना के सफल संचालन हेतू उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना
- **मनरेगा** योजना की महत्ता एवं कार्यशीलता पर प्रकाश डालना

5. Noteworthy Contribution In The Field Of Proposed Work

भारत एक प्राचीन तथा विशाल देश है, पिछले लगभग 65 वर्षो के पश्चात् यहॉ जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। बढ़ती जनसंख्या का सर्वाधिक नकारात्मक पहलु बढ़ती गरीबी है। सरकार की वृहद योजना मनरेगा जो पूरे भारत में कार्यरत है, जिसके द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रो में बेरोजगारी, गरीबी, पलायन तथा असमानता जैसी मूलभूत समस्याओं का निकारण किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारत के 6 लाख से अधिक गॉवों में न केवल वयस्क पुरूषो का अपितु महिलाओं तथा विकलांगो को भी रोजगार के अवसर निरंतर उपलब्ध कराये जा रहे है, जिससे गॉव से शहर की ओर हो रहे पलायन पर अंकुश दिखाई देता है।

मनरेगा योजना अकुशल वयस्क श्रम को अकर्मण्य होने से बचाती है तथा योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि, प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय में वृद्वि का कारण बन रही है जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर पर सुधार देखा जा सकता है। यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस योजना के तहत मुख्य रूप से सुखा, जंगलों का विनाश और भूमि कटाव जैसी जन समस्याओं को संबोधित किया गया है, जिनके कारण बड़े पैमाने में गरीबी फैल रही है चुकिं यह योजना सम्पूर्ण भारत में कार्यरत है, परिणाम स्वरूप कुछ समस्या का आना स्वभाविक है परंतु भारत सरकार इसकी कमियों, समस्याओं को ध्यान में रखकर बढ़ती हुई कार्यो की मॉग, रूचिंयॉ तथा ग्रामीणों में कार्यो की कमी के कारण भारत सरकार ने मनरेगा–2 अर्थात् मनरेगा के कार्यो में अधिक से अधिक नवीन कार्यो का समावेश किया है तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने राज्य में इस योजना के कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है, जिसकी सहायता से ग्रामीणों को कार्य ज्यादा दिनों के लिए उपलब्ध हो रहे है। मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध होने वाले रोजगार, गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है।

6 लाख से अधिक गांवो वाले भारत देश के लिए बनाई गई यह योजना ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण विकास के दृष्टीकोण से बहुत उपयोगी है। यह योजना सैद्वांतिक स्वरूप से अच्छे एवं प्रभावी उद्देश्यो को अपने मे समाहित की हुई है। इसके माध्यम से ग्रामीणों मे गरीबी का प्रतिशत कम होता जा रहा है

इस प्रकार मनरेगा योजना में कई ऐसे पहलू है जिनके आधार पर इसे ''**जनता का कानून**'' कहा जाता है जो ''**जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।**'' यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

6. Proposed Methodology

शोध प्रविधी

एक शोधकर्ता अपने शोध आंकड़ो को शोध का आधार मानकर कार्य करता है। बिना आंकड़ो के शोध कार्य वास्तव में एक अपंग प्राणी की भांति है। शोधकर्ता का मुख्य लक्ष्य ऐसे तथ्य सामग्री का संकलन करना होता है, जो उसकी परिकल्पनाओं का या तो समर्थन करती हो या पहले से बनाई गई उपकल्पना को अस्वीकार करती हों। शोध पद्धति की सहायता से आंकड़ो का संकलन किया जाता है, ताकि उसके माध्यम से किसी शोध के परिणामों की सार्थकता निर्धारित की जा सकें।

प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्वति

प्रस्तावित शोध की अध्ययन पद्वति निम्नांकित भागों में विभक्त है :—

1. **अध्ययन क्षेत्र का चुनाव**
2. **अध्ययनगत इकाई :—** प्रस्तुत अध्ययन में अध्ययनगत इकाई के रूप में राजनांदगॉव जिले में मनरेगा के अंर्तगत कार्यरत मजदूरों, लाभार्थीयो, मनरेगा योजना से संबंधित अन्य ग्रामीण प्रतिनिधियों को इकाई के रूप में किया गया है ।
3. **उत्तरदाताओं की प्रकृति :—** उत्तरदाताओं की प्रकृति के अंतर्गत मनरेगा के लाभार्थीयों तथा मनरेगा योजना का संचालन करने हेतु नियुक्त अधिकारीयों को सम्मिलित किया गया है ।
4. **उत्तरदाताओं का चुनाव :—** प्रस्तावित अध्ययन हेतु अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण मजदूरों तथा मनरेगा योजना संचालनकर्ता का चुनाव बहुस्तरीय निर्देशन के द्वारा किया गया है। जिसके अंतर्गत जिले के कुल 9 विकासखण्ड़ों में से 300 व्यक्तियों का चुनाव दैव निर्दशन के द्वारा किया जाएगा ।

5. **तथ्य संकलन की पद्वति, प्रविधी एवं उपकरण :–** प्रस्तावित शोध कार्य हेतु तथ्यों का संकलन दो प्रकार से किया जाएगा –

1. प्राथमिक समंक
2. द्वितीय समंक

प्राथमिक समंक :–

प्राथमिक समंको को मौलिक समंक भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्वयं शोधकर्ता द्वारा उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्रित किये जाते है। यह किसी शोध के मुख्य आधार होते है। उत्तरदाताओं की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक समंको का संकलन करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची तथा प्रश्नावली का प्रयोग किया जावेगा साथ ही साथ शोध कार्य के दौरान अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों से समुहवार्ता व अवलोकन पद्वति के द्वारा प्राथमिक समंकों का संकलन किया जाएगा ।

द्वितीयक समंक :–

वे समंक होते है जिनका संकलन पहले किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता उन्हें अपने प्रयोग में लाता है। अनुसंधान करते समय यह निश्चित करना पड़ता है कि मौलिक सामग्री एकत्रित करनी है या प्रकाशित या उपलब्ध सामग्री से ही कार्य अग्रेषित किया जाएगा। इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में गरीबी उन्मुलन तथा मनरेगा से संबंधित विभिन्न शासकीय प्रपत्र व दस्तावेज, विभिन्न शोध पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों में समय–समय पर प्रकाशित तथ्य शामिल है ।

7. Expected Outcome Of The Proposed Work

"भारत गॉवों का देश है"। भारत में निवासरत अधिकांश ग्रामीण, मजदूरी या कृषि का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करते है परंतु इसके पश्चात् भी ग्रामीणों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। कार्य प्राप्त करने हेतु ग्रामीण अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन करते है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे राज्य में मजदूरों की कमी पायी गई।

उक्त समस्या के आधार पर तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से **मनरेगा** की सफलता तथा विसफलता को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता द्वारा प्रस्तावित शोध कार्य किया जाएगा जिसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र में **मनरेगा** योजना द्वारा उपलब्ध कराये गये रोजगारो तथा **मनरेगा** द्वारा किये गये कार्यो का आकलन होगा जिससे क्षेत्र विशेष के विकास पर प्रकाश डालते हुए **मनरेगा** द्वारा किये गये कार्यो तथा विकास का तुलनात्मक अध्ययन भी इस शोध कार्य में सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ अध्ययन क्षेत्र में योजना की समस्या का पता लगाकर उसके सफल संचालन हेतु उपयुक्त सुझाव सुझाएँ जाऐंगें ताकि **मनरेगा** योजना की महत्ता एवं कार्यशीलता का एक प्रमाप निर्धारित किया जा सकें।

शोधकर्ता के शोध के द्वारा सरकार की इस बहुयामी योजना **मनरेगा** से ग्रामीणों को जोड़ने के लिए तथा उनकी समस्याओं का सामाधान करने के लिए एक प्रबल प्रयास किया गया है। ग्रामीणों में गरीबी उन्मूलन करने हेतु, उनकी बेरोजगारी दूर करने तथा समाज में उन्हें एक स्थान प्रदान करने के लिए शोधकर्ता द्वारा यह शोध कार्य किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण **मनरेगा** के महत्व को समझें और इस महत्वपूर्ण योजना में कार्यरत होकर अपनी गरीबी, बेरोजगारी तथा पलायन जैसी समस्याओं का निराकरण करें।

रोजगार उन्मुखी तथा गरीबी उन्मूलन हेतु बनाई गई **मनरेगा** योजना अपने द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यो तथा उन कार्यो के सफल परिणामों के आधार पर यह योजना आगामी वर्षो में ग्रामीण रोजगार के प्रतिशत में वृद्धि करते हुए ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से भी हमारे देश के विकास के मार्ग में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी जिस पर चलकर देश विकास की ओर अग्रसर होगा।

मनरेगा के महत्व तथा लाभों को समाज तक पहुचाने हेतु शोधकर्ता द्वारा अपने शोध कार्यक्रम को निम्न अध्यायों में विभक्त किया गया है :–

" प्रस्तावित शोध कार्य की अध्यायीकरण योजना "

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा के कार्यो का मूल्यात्मक अध्ययन
(राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)

अध्याय – 1 परिचयात्मक पृष्ठभूमि

1.1 गरीबी एवं गरीबी रेखा
1.2 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
1.3 मनरेगा एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
1.4 शोध साहित्य का पूर्वाअवलोकन
1.5 शोध क्षेत्र : छत्तीसगढ़ का राजनांदगॉव जिला

अध्याय – 2 शोध उद्देश्य एवं परिकल्पना

2.1 शोध उद्देश्य
2.2 शोध परिकल्पना का अर्थ
2.3 अच्छी शोध परिकल्पना के लक्षण
2.4 इस शोधकर्म की परिकल्पना

अध्याय – 3 शोध प्रविधी

3.1 शोध प्रविधी का अर्थ
3.2 शोध प्रविधी की विशेषताएॅ
3.3 शोध प्रविधी के प्रकार
3.4 शोध कार्य हेतु प्रयुक्त शोध प्रविधी

अध्याय – 4 मनरेगा : कल, आज और कल

4.1 मनरेगा की पृष्ठभूमि
4.2 केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ में मरनेगा की दशा एवं दिशा
4.3 राजनांदगॉव जिले में मनरेगा की भूमिका

अध्याय– 5 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

5.1 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अर्थ
5.2 केन्द्र सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाएँ
5.3 छत्तीसगढ़ शासन की गरीबी उन्मूलन योजनाएँ
5.4 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता एवं विफलता
5.5 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के उपाय

अध्याय– 6 मनरेगा का मूल्यांकन

6.1 मनरेगा की सफलता
6.2 मनरेगा के मार्ग में प्रमुख बांधाएँ
6.3 मनरेगा से अपेक्षाएँ
6.4 मनरेगा को प्रभावी बनाने के उपाय

अध्याय– 7 शोध के निष्कर्ष

संदर्भ ग्रंथ सूची एवं संबंधित साहित्य

शोध के परिणामों को सत्यता से परिलक्षित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा शोध की निम्नलिखित परिकल्पनाएँ बनाई गई है, जिन्हे शोध के दौरान महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा :—

शोध की परिकल्पनाएँ

किसी शोध की परिकल्पना 'अनुसंधान' का महत्वपूर्ण चरण होती है। शोध परिकल्पना एक कार्यकारी आधार होती है, जो कि शोधार्थी द्वारा किये जा रहे शोध कार्य को एक दिशा प्रदान करती है। शोध परिकल्पना को एक ऐसी परिकल्पना कहा जाता है जिसका परीक्षण शोध कार्य के दौरान किया जाता है

''उपकल्पना/परिकल्पना सिद्धांत और शोध कार्यो के बीच एक आवश्यक कड़ी है जो अतिरिक्त ज्ञान की खोज मे सहायक होती है।''

प्रस्तावित शोधकर्म की परिकल्पनाएँ :—

1. **मनरेगा** कार्य योजना बेरोजगारी दूर करने में कामयाब होगी।
2. शोध क्षेत्र में ''ग्रामीण गरीबी उन्मूलन'' कार्यक्रम के तहत **मनरेगा** की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
3. **मनरेगा** से गाँवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा जिससे रोजगार के दूसरे अवसर प्राप्त होगें।

8. Bibliography

संबंधित साहित्य का अध्ययन संदर्भ सूची

1. Ambasta, P; Vijay Shankar, P.S. And Shah Mihir (2008), "Two Year Of NREGA : The Road Ahead " Economic & Political Weekly, February 23-29, Vol XIIII, No. 8, PP,41-50…..

2. Anand V 2008. Cited In Panchayati Raj Update By Mohanty B" Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Act : A Woman Programme….From<Http:Knowleage.Nrega.Net/201/01/NREGA_A_Woman's Programme.Pdf> (Reterieved On 19/02/2011)….

3. Badodiya, S.K. Khushwah, R.S. And Shakya, S.K. (2011). Impact Of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mnrega) On Ppverty Alleviation . Raj.J. Extn. Edu. 19: 206-209…

4. CAG (2007) " Draft Performance Audit, Of Implementation Of Nrega " Office Of The Principal Director Of Audit,, Economic And Service Ministers,, New Dehli…

5. Chakravarthy Anupam , Tiwari (July 2010). " After Modi Sniffs Corruption In NREGA, Delhi Flags State Dossier" Indian Express , Ahemedabad , July 27,2010,PP1,2…

6. CSE (2008) " Mnrega Oppportunities And Challenges " By Natural Resource Management And Livelihood Unit , Center For Science And Environment (Cse), New Delhi..

7. Dreze J 2006 "National Emplotment Guarantee Inaction " , The Hindu,12septmber..Fromwww.Hindu.Com /2006/09/12/Stories,,,(Retrieved On 12/03/2011)

8. Grag S 2008 Economic Impat Of (NREGA) Programme On Woman .. M.Sc Thesis , Unpublished . Maharana Pratap University Of Agriculture And Technology, Udaipur..

9. Honnakeri , P.M. and kote , A.K. (2012) . The Impact Of MNREGA Scheme On Rural-Urban Migration In Rural Economy With Special Reference To Gullbarga District In Karnataka State. Indian Streams Research Journal , Vol.2 Issue.I ,Pp.1-4..

10. Jaswal Anshuman And Ministry Paulomee(2003) .."Will Nrega Ensure Security Against Hunger ? Disha Ahmedabad…

11. Joshi Varsha , Surjit Singh , Joshi K.N. (Spet. 2008)"Evaluation Of Nrega In Rajasthan " , Ids Jaipur..

12. Kannapiram, C. 1992 Financial Impact Of Irdp On Rural Poverty In India . Journal Of Rural Development. 11: 789-801..

13. Prasad , M.R. IAMR(2008) "All India Report On Evaluation Of NREGA : A Survey Of Twenty District " IMAR , Narela ,New Delhi.

14. Reetika Khera, Nayak Nandini (2009) "Woman Workers Perceptions Of The Nrega " Economic & Political Weekly , October 24-30, 2009 Vol. Xliv No 43, Pp 49..

15. Rengasamy , K And Sasi Kumar (2011) . State Level Performance Of Mnrega In India : A Comparative Study International Multidisciplinary Research Journal, 1(10): 36-40.

16. Vanik Anish And Siddhartha (2008) "Bank Payment : End Of Corruption In Nrega " Economic Weekly , 26-2 May ,2009 Vol Xl Iii No. 17, Pp 33-39.

17. Siddhanta Priyadarshan (2010) "Nrega Falls Way Short Of Targets" Indian Expess, Ahemdabad Edition , July 21 , 2010 Pp.17..

संदर्भ–सूची

शोध ग्रंथ एवं पुस्तकें :–

1. आनंद प्रकाश मिश्र – ग्रामीण निर्धनता, साहित्य भवन,आगरा, **1998**
2. अनन्या चंद्र – गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों के कुछ मुद्दें, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, **2001**
3. बम्हदेव शर्मा – गरीबी का मकड़जाल, साहित्य भवन,आगरा, **1999**
4. छेद खुदाई – भारतीय ग्रामीण कल्याण, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, **2001**
5. डॉ.बी.एल. माथुर – भारतीय अर्थव्यवस्था, साहित्य भवन,आगरा, **1997**
6. डॉ. बी.एल. फाड़िया – शोध पद्वतियॉ, साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा, **2004**
7. डॉ. बी.एम जैन – शोध प्रविधी एवं क्षेत्रीय तकनीक, कालेज बुक डीपोट,जयपुर, **2001**
8. डॉ. डी.सी. पंत – भारत में ग्रामीण विकास, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, **1998**
9. डॉ. गणेश पाण्डेय एवं अरूणा पाण्डेय– शोध प्रविधी, राधा पब्लिकेशन,दिल्ली, **2007**
10. डॉ. जी.के. अग्रवाल – सामाजिक समस्याऍं, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा,**1998**
11. डॉ. हीरालाल – जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, **2003**
12. डॉ. मामोरिया एवं द्विवेदी – भारत की आर्थिक समस्याऍं, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा, **2005**
13. डॉ. मामोरिया एवं जनै – भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा, **1999**
14. डां. मिश्र जगनाथ – भारतीय आर्थिक विकास की नयी प्रवृतियॉ, विकास पब्लिकेशन हाउस,दिल्ली, **1998**
15. डां. ओ.एस. श्रीवास्तव – संवृद्वि एवं विकास का अर्थशास्त्र, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, **2005**
16. डां.पदमावती – ग्रामीण निर्धनता एवं निर्धनता कार्यक्रमों का मूल्यांकन, तिवारी प्रकाशन,दिल्ली, **2002**
17. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी – रिसर्च मैथ्डोलाजी, कालेज बुक डीपोट,जयपुर, **1998**
18. डॉ. संजय तिवारी – सामाजिक विज्ञान में शोध प्रविधी, साहित्य भवन,आगरा, **2000**
19. डॉ. वी.सी. सिन्हा – भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सांख्यिकी, एस.बी.डी.पी. पब्लिशिंग हाउस,मथुरा ,**2005**
20. लुईस क्लोरेंस– असमानता और गरीब, साहित्य भवन,आगरा, **2003**
21. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम **2005**
22. महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम **2011**

23. प्रो.गुप्ता एवं सक्सेना – भारत की आर्थिक समस्याएँ, नवयुवक साहित्य भवन,आगरा, 2006
24. रूददत्त एवं सुदंरम – भारतीय अर्थव्यवस्था, राम निगम प्रकाशन,दिल्ली, 2007
25. सुगन चंद फलवार एवं तेजराम मीणा– निर्धनता उन्मुलन एवं ग्रामीण विलस।
26. एस.चंद – भारतीय अर्थव्यवस्था, राम निगम प्रकाशन,दिल्ली, 2006
27. सुरज देव वसंत – जनसंख्या भूगोल, कैलाश पुस्तक सदन,भोपाल, 2005
28. एस.पी. सिंह – सांख्यिकी,सिद्यांत एवं व्यवहार, एस.चंद एण्ड कम्पनी लिमी.नई,दिल्ली, 2008
29. एस.पी. सिंह – भारतीय विकास एवं नियोजन, एस.चंद एण्ड कम्पनी लिमी.नई,दिल्ली, 2008
30. सिंह एवं भट्टाचार्य – भारतीय समाजिक समस्याएँ, शिक्षा साहित्य प्रकाशन,मेरठ, 2009
31. टाम राईट एवं हर्ष गुप्ता – ग्रामीण गरीब नजरअंदाज, 2011

The Atlantic Book Review

- Economics of development and planning – K.R. Gupta (Vol.19788126910106)
- Economic Growth Models -K.R. Gupta (Vol.19788126913381)//2005
- The General Theory of Employment , interest and money –John Maynard Keynes 2006
- India Rising (But who will make it Huppen?)- J.N. Rampal Vol.1 -978812480269/..2010

शोध पत्र एवं पत्रिकाएँ :–

1. ''तेन्दुलकर समिती की गरीबी पर रिर्पोट **2009**''
2. ''छत्तीसगढ जनसंख्यां रिपोर्ट **2011**''
3. ''दिशा एवं निर्देशन रिपोर्ट'' ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित **2010**
4. ''रिसर्च लिंक''शोध पत्रिका,इन्दौर, **2010**
5. ''कुरूकक्षेत्र'' मासिक पत्रिका रोजगार स्थिती नवंबर **2012**
6. ''इंडिया टुडे'' भारत की योजना मनरेगा दिसंबर **2012**
7. ''योजना आयोग'' की गरीबी पर रिर्पोट **2010**

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं :–

❖ **दैनिक भास्कर –**

- कैलोरी का सेवन कसौटी गरीबी रेखा से निचे 50 फिसदी भारतीय 09.12.2012।
- 17 रू.रोज से भी कम पर जीते हैं 10 प्रतिशत ग्रामीण 02.08.2012

❖ **नवभारत टाईम्स :–**

- मनरेगा और गरीबी 03.04.2013

❖ **भास्कर भूमि :–**

- महंगा पड़ा मनरेगा में काम करना 09.10.2012

❖ **टाईम्स ऑफ इंडिया :–**

- 8 भारतीय राज्यों के 26 सबसे गरीब आफ्रिकी देशों से भी अधिक गरीब है।
- 07.12.2010।
- अधिक गरीब भारत में आफ्रिका से भी 07.13.2010
- भारत की गरीबी 2015 तक 51 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक गिर जायेगी
- 16.10.2012

Net website

www.google.com

www.gov.in.com

www.zprajnandgaon.gov.in

9. List Of Published Papers Of The Candidate

- Nil

शोध निर्देशक

डॉ. जी.डी.एस.बग्गा
विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) चंदुलाल चन्द्राकर शासकीय
कला व वाणिज्य महाविद्यालय
धमधा, जिला – दुर्ग (छ.ग.)

Dr. G. D. S. Bagga
Professor of Commerce
C.L.C. Govt. College.
DHAMDHA, Distt.-Durg (C.G.)

सह–निर्देशक

डॉ. आर.एन. सिंह
प्राचार्य, शास. दिग्विजय
महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

शोधार्थी

आकाश वैष्णव

शोध केन्द्र

शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

दिनांक :–